पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिनय कुमार दास

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या 7089

28 नवंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या 192 दिनांक 13.02.2023 सही है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून - याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, बाद में उसे स्वीकृत पद पर चपरासी के विरुद्ध कार्य परिवर्तन प्रतिष्ठान से नियमित प्रतिष्ठान में शामिल कर लिया गया - प्रतिवादियों ने उसकी सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की राशि की वसूली के संबंध में एक पत्र जारी किया।

निर्णय: किसी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद कोई वसूली नहीं की जा सकती है, यदि उसे लाभ गलत तरीके से दिए गए हैं, उक्त कर्मचारी की ओर से किसी गलत बयानी के कारण नहीं, बल्कि संबंधित विभाग की गलती के कारण, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता से ग्रेच्युटी की राशि वसूलने से रोक दिया जाता है - यदि वसूल की गई है, तो उसे वापस करने का निर्देश दिया जाता है - रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(पैराग्राफ 5 से 8)

न्याय दृष्टान्त

सैयद कादिर बनाम बिहार राज्य, (2009) 3 एससीसी केयर पेज नंबर गायब हैं; साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) सप्ल.1 एससीसी 80; श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ, (1994) 2 एससीसी 52; बी गंगा राम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, (1997) 6 एससीसी 139; पुरुषोत्तम लाल दास बनाम बिहार राज्य, (2006) 11 एससीसी 492; बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

बनाम बिजय बहादुर, (2000) 10 एससीसी 99; बी.जे. अक्कारा बनाम भारत सरकार विश्वविद्यालय, (2006) 11 एससीसी 7089 केयर पेज नंबर; साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) सप्ल. 1 एससीसी 18; पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह, (2015 थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससीसी 536—भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

मुख्य शब्दों की सूची

ग्रेच्युटी की राशि, कोई वसूली नहीं, सेवानिवृत्ति, अनुकंपा नियुक्ति

प्रकरण से उत्पन्न

प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र क्रमांक 192 दिनांक 13.02.2023 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री हर्षवर्धन सहाय, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री सुशील कुमार, जीपी-22; श्री के. के. सिंह, जीपी-22 के लिए सहायक।

महालेखाकार की ओर से: श्री राम यश सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला No.7089**

बिनय कुमार दास पुत्र विजय चंद्र दास, गाँव नागा टोला के निवासी, पी. ओ. के. हाट, थाना-
के. हाट, जिला-पूर्णिया।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. संयुक्त सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अधीक्षण अभियंता, सड़क, निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, पूर्णिया।
4. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णिया, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. कोषागार अधिकारी, पूर्णिया।
6. महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री हर्षवर्धन सहाय, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सुशील कुमार, जीपी-22; श्री के.के. सिंह जीपी-22 के
एसी
महालेखाकार के लिए : श्री राम यश सिंह, विद्वान अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख:28-11-2023

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई

रु:-

“1. कि यह रिट आवेदन परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए है:

i इस याचिका के अनुलग्नक-1 में निहित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की तारीख (20.05.1986) से चपरासी के पद पर नियमित प्रतिष्ठान में याचिकाकर्ता को नियमित करना।

ii पत्र संख्या 192 को रद्द करें। दिनांक 13.02.2023, जिसके तहत और जिसके द्वारा रु. 77,475.00, याचिकाकर्ता की उपदान राशि में से कटौती की गई है।”

2. शुरुआत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया है, बहुत पहले 03.06.2022 को, फिर भी, प्रतिवादी कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल, पूर्णिया द्वारा जारी दिनांक- 13.02.2023 के पत्र के माध्यम से ग्रेच्युटी (उपदान) राशि से रु. 77,475/- की राशि की कटौती करने की मांग कर रहे हैं।

3. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने पैराग्राफ सं.10, जवाबी शपथपत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को शुरु में अनुकंपा के आधार पर, अस्थायी रूप से, 20.05.1986 को नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उसे दिनांक- 20.02.2001 से प्रभावी चपरासी के स्वीकृत पद के खिलाफ कार्य परिवर्तन प्रतिष्ठान से नियमित प्रतिष्ठान में शामिल कर लिया गया था, इसलिए वह वित्त विभाग के संकल्प दिनांक 23.09.2016 के माध्यम से दिए गए लाभों का हकदार नहीं है, जो उसे गलत तरीके से दिया गया है, इस प्रकार रु. 77, 475/- की राशि की वसूली करने में कोई अवैधता नहीं है।

4. इस न्यायालय ने पाया कि वसूली के संबंध में कानून अब एकीकृत नहीं है और इसे अच्छी तरह से तय किया गया है (2009) 3 एस. सी. सी. (सैयद कादिर बनाम बिहार राज्य) में रिपोर्ट किए गए निर्णय; (1995) पूरक 1 एस. सी. सी. 80 (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य); (1994) 2 एस. सी. सी. 52 (श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ); (1997) 6 एस. सी. सी. 139 (बी. गंगा राम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक); (2006) 11 एससीसी 492 (पुरुषोत्तम लाल दास बनाम बिहार राज्य); (2000) 10 एससीसी 99 (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बिजय बहादुर); (2006) 11 एससीसी 7089 (बीजे। अक्कारा बनाम भारत सरकार

विश्वविद्यालय) और (1995) पूरक।1 एस. सी. सी. 18 (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य) और (2015) 4 एस. सी. सी. 334 (पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह) में रिपोर्ट किया गया।

5. इस मोड़ पर, यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक और निर्णय का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त समझता है। थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. सी. 536 में रिपोर्ट किया गया। पैराग्राफ सं. 9, 11 और जिनमें से 14 से 16 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“9. इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कर्मचारी की किसी गलत प्रस्तुति या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था या यदि नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की एक विशेष व्याख्या के आधार पर ऐसा अतिरिक्त भुगतान किया गया था, जो बाद में गलत पाया जाता है, तो परिलब्धियों या भत्तों का ऐसा अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य नहीं है। वसूली के खिलाफ यह राहत कर्मचारियों के किसी भी अधिकार के कारण नहीं दी गई है।

लेकिन साम्य रूप में, यदि वसूली का आदेश दिया जाता है तो कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई से राहत प्रदान करने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए कर्मचारी को राहत दिया गया है। इस न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मामले में, यह साबित हो जाता है कि किसी कर्मचारी को जानकारी थी कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था, या ऐसे मामलों में जहां त्रुटि का पता लगाया जाता है या गलत भुगतान

के थोड़े समय के भीतर सुधार किया जाता है, मामला न्यायिक विवेक के दायरे में होने के कारण, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए आदेश दे सकती हैं।

11. कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार में इस न्यायालय ने एक समान प्रश्न पर विचार किया जो निम्नानुसार है:”

27. विचार करने के लिए अंतिम प्रश्न यह है कि क्या दिनांकित 7-6-1999 परिपत्र की गलत व्याख्या/समझ के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के खिलाफ राहत दी जानी चाहिए। इस न्यायालय ने एक कर्मचारी से परिलब्धियों/भत्तों के अतिरिक्त गलत भुगतान की वसूली के खिलाफ लगातार राहत दी है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य [1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 18:1995 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 248], श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ [(1994) 2 एस. सी. सी. 521:1994 एससीसी (एल एंड एस) 683:(1994) 27 एटीसी 121], भारत संघ बनाम एम. भास्कर [(1996) 4 एससीसी 416:1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 967] और वी. गंगाराम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक [(1997) 6 एस. सी. सी. 139:1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1652]):

(क) अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की ओर से किसी भी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण नहीं किया गया था।

(ख) ऐसा अतिरिक्त भुगतान नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की एक विशेष व्याख्या के आधार पर किया गया था, जो बाद में गलत पाया जाता है।

28. इस तरह की राहत, अतिरिक्त भुगतान की वसूली को वापस रोकने के लिए, अदालतों द्वारा कर्मचारियों के किसी भी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि साम्य रूप में, न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों को उन कठिनाइयों से राहत देने के लिए दी जाती है जो वसूली लागू होने पर होंगी। एक सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से जो सेवा के निचले स्तर पर होता है, वह अपने परिवार के रखरखाव के लिए जो भी वेतन प्राप्त करता है, उसे खर्च करता है। यदि वह एक लंबी अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करता है, तो वह इसे खर्च करेगा, वास्तव में यह मानते हुए कि वह इसका हकदार है। चूंकि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कोई भी बाद की कार्रवाई उसकी अनुचित कठिनाई का कारण बनेगी, इसलिए उस ओर से राहत दी जाती है। लेकिन जहां कर्मचारी को पता था कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था, या जहां त्रुटि का पता चला है या गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर ठीक किया गया है, तो अदालतें वसूली के खिलाफ राहत नहीं देंगी। मामला न्यायिक विवेकाधिकार के दायरे में होने के कारण, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर वसूली (पुनर्प्राप्ति) के खिलाफ ऐसी राहत देने से इनकार कर सकती हैं।

29. इसी सिद्धांत पर, पेंशनभोगी यह निर्देश भी ले सकते हैं कि गलत भुगतान की वसूली नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सेवाकालीन कर्मचारियों की तुलना में पेंशनभोगी अधिक नुकसानदेह स्थिति में होते हैं। अतिरिक्त गलत भुगतान की वसूली के किसी भी प्रयास से उन्हें अनुचित कठिनाई होगी। याचिकाकर्ता अतिरिक्त भुगतान के संबंध में किसी भी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के दोषी नहीं हैं।

कार्यान्वयन विभागों द्वारा गलत समझ के कारण वृद्धि करने के उद्देश्य से, एन. पी. ए. को न्यूनतम वेतन में जोड़ा गया था। इसलिए हमारा विचार है कि उत्तरदाता दिनांक 11-9-2001 के स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र के जारी होने तक दिनांक 7-6-1999 के परिपत्र के अनुसरण में पेंशन के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं करेंगे। जहां तक परिपत्र दिनांक 11.09.2001 के बाद किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान का संबंध है, जाहिर है कि भारत संघ अतिरिक्त राशि की वसूली करने का हकदार होगा क्योंकि उक्त परिपत्र की वैधता को बरकरार रखा गया है और पेंशनभोगियों को पहले की गई गलत गणनाओं के संबंध में नोटिस पर रखा गया है।”

14. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने या धोखाधड़ी के कारण, अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है। अपीलार्थी 31.03.1999 को सेवानिवृत्त हो गया है। वास्तव में, उत्तरदाताओं का मामला यह है कि अतिरिक्त भुगतान केरल सेवा नियमों की व्याख्या करने में गलती के कारण किया गया था, जिसे बाद में महालेखाकार द्वारा इंगित किया गया था।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उनकी सेवानिवृत्ति के दस साल बीतने के बाद उक्त वेतन वृद्धि की वसूली का प्रयास अनुचित है।

16. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। खंडपीठ का दिनांक 02.03.2009 का निर्णय और आदेश और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 05.01.2006 का आदेश, और केरल के मुख्यमंत्री के लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा पारित 26.06.2000 का आदेश और

दिनांकित 09.10.1997 की वसूली सूचना को इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।
लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।”

6. नतीजतन, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामला आवृत्त (आवरण) है न केवल ऊपर निर्दिष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के एक समूह द्वारा, बल्कि रफीक मसीह (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ सं. 18 जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया है:-

“18. उन सभी कठिनाइयों की स्थितियों को अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर नियंत्रित करती हैं, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान किया गया है, जो उनकी पात्रता से अधिक है। चाहे जो भी हो, ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के आधार पर, हम, एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी:-

- (i) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
- (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली के आदेश से।
- (iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले, पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
- (iv) ऐसे मामलों में वसूली जहां एक कर्मचारी को गलत तरीके से एक उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक किया गया है, और उसी के अनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे किसी निम्न

पद के खिलाफ काम करने के लिए उचित रूप से आवश्यक किया गया हो।

(v) किसी भी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, जो यह अभिनिर्धारित करता है कि कोई वसूली किसी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद किया जा सकता है, यदि उसे गलत तरीके से लाभ दिए गए हैं, न कि उक्त कर्मचारी की ओर से किसी गलत प्रतिनिधित्व के कारण, लेकिन संबंधित विभाग की गलती के कारण, यह न्यायालय पाता है कि कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल, पूर्णिया द्वारा जारी किया गया 13.02.2023 दिनांकित आदेश कानून के विपरीत है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है। प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता से रु.77,475/- की उपरोक्त राशि की वसूली करने से रोक दिया जाता है और यदि वही राशि वसूली की गई है, तो उसे आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

8. रिट याचिका की अनुमति है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमुर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।